सम्मान का सवाल इसके साथ जुड़ गया है। इसलिए हम संकल्पबद्ध हैं कि फिजूलखर्ची नहीं करेंगे लेकिन हम भव्यता का और भारत की आतिथ्य परंपरा का पूरा ध्यान रखेंगे। खेल के संचालन में खिलाड़ियों को कोई शिकायत न रहने पाए इसका भी हम पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे, यह मैं सदन से निवेदन करना चाहती हूं। लेकिन यह ध्यान रहे कि समय हमें बहुत कम मिला है और चुनौती हमें बड़ी दी गई है, इसलिए हम तो सदन का आशीर्वाद चाहते हैं कि इस चुनौती का हम मुकाबला कर सकें और समय कम होते हुए भी सर्वोत्तम तरीके से इन खेलों को संचालित कर सकें।

Private Catering on Trains

*564. SHRI BHAGATRAM MANHAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of trains on which private catering has been allowed;

(b) the details of contractors and the other trains on which the same contractors have been permitted to do catering, without calling for tenders/bids; and

(c) the number of complaints received against these contractors from Members of Parliament and other VIPs and the action against them ?

MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) 124 pairs of trains.

(b) Details of 51 private contractors managing pantry car services are given in Statement–I.

Details of pantry car contractors permitted to do catering on other trains without calling for tenders/bids and reasons thereof are given in Statement–II.

(c) Nine complaints were received in the period from March 2000 to July 2001. Punitive action has been taken against the licensees including imposition of fines in case of substantiated complaints.

Statement-I

List of the Contractors Managing Pantry Cars

S. No.	Names	S. No.	Names
(1)	(2)	(1)	(2)
1.	A. A. Caterers	27.	Satkar Caterers
2.	A. K. Ghosh	28.	S. C. Ctg. & Vdg. Co.
3.	A. B. C. Enterprise	29.	Sindoor Caterers
4.	Ahaar Caterer	30.	Kunjlal Das
5.	Arenco Catering	31.	Singh Caterers
6.	Bharat Catering Corp.	32.	T. V. Mohd. Ali
7.	Bhol Caterers	33.	V. P. Dewadkar
8.	Boon Caterers	34.	Vardan Caterers
9.	C. K. K. Maidoo	35.	EVS Catg. Coffee Corner
10.	CKK & NBK Caterers	36.	NBQ Ctg. & Vdg. Co-op.
11.	Doon Caterers	37.	Vivekanand Dass & Co.
12.	E. A. Karunakaran	38.	P. K. Associates
13.	Excellant Caterers	39.	P. K. Shaffi
14.	Food World	40.	P. R. Caterers
15.	Gati & Co.	41.	Poorvanchal Caterers
16.	Golden Caterers	42.	R. C. Goel
17.	Good Food	43.	R. K. Associates
18.	Hakim Chand D. Chotai	44.	Raman Deka
19.	Hotel Ambuj Pvt. Ltd.	45.	Roop Caterers
20.	J. K. Ghosh	46.	S. Pandian
21.	K. Balyakoti	47.	Baba Caterers,
22.	K. K. Sharma	48.	Ex. Servicemen
23.	K. M. A. Caterers	49.	S. S. Caterers
24.	Kwality Caterers	50.	Mahesh H. Caterers & Co.
25.	M. Pusanna	51.	Midwest Caterers
26.	Mahesh Caterers		

Statement-II

Details of Contractors Permited to do Catering on Trains without Calling Bids/Tenders

S. No.	Train	Licensee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5623/5624 Guwahati-Cochin Express	Shri Ramen Deka	Existing contractor of 5625/5626 Guwahati-Bangalore was asked to manage catering services in 1998 as the rakes of two trains were integrated.
2.	5647/5648 Guwahati-Dadar Express	M/s NBQ Catering & Vending & Coop	Existing contractor of 5645/5646 Guwahati-Dadar via Katihar was allowed to manage catering services on this train which is running via Malds Town, thereby, increasing frequency from bi-weekly to tri-weekly.
3.	2679/2680 Chennai-Coimbatore Intercity	M/s. Golden Caterers	M/s Golden Caterers was managing catering services on Coimbatore Shatabdi, which was cancelled in July 1999 and intercity train was introduced. Railway allowed same contractor temporarily and fresh notification was issued to call for applications. The licensee has approached court of law and obtained stay orders.
4.	6507/6508 Bangalore-Jodhpur (Summer Special)	Shri P. K. Shaffi	The licensee was allowed to manage catering services on this train, in July 2000, in lieu of 2637/2638 Kudai Express, which was cancelled in 1998 due to gauge conversion. The train has

(1)	(2)	(3)	(4)
			since been made regular. Fresh notification was issued to call for applications. The licensee has approached court of law and obtained stay orders.
5.	2711/2712 Vijyawada-Chennai, Pinakini Express	M/s. ABC Enterprises	Allotment was made by Ministry of Railways in December 1992 as a special case.
6.	2713/2714 Secundrabad-Vijyawada Satavana Express	M/s. ABC Enterprices	Allotment was made by Ministry of Raiways in December 1992 as a special case.
7.	7085/7086 Bangalore-Secundrabad Express	M/s. R. K. Associates	Existing contractor of 2703-04, Howrah-Secundrabad, Falaknuma Express in 1998 was asked to manage catering services as the rakes of two trains were integrated.
8.	7017/7018 Secundrabad-Rajkot Express	M/s. Midwest Caterers	Existing contractor of 7061-62, Secundrabad-Behlapur, Shirdi Express was asked, in Feb. 1998, to manage catering services as the rakes of two trains were integrated. The Shirdi Express train was subsequently cancelled in March 1998.

श्री भगत राम मनहर : उपसभाध्यक्ष महोदय, अक्सर देखा गया है कि रेलवे बोर्ड के सदस्यगण हवाई यात्राओं में विश्वास करते हैं और ट्रेनों में यात्रा करना नहीं चाहते हैं। मुझे खुशी है कि उन्हें संजय दृष्टि प्राप्त है और वे हवाई जहाज एवं अपने दफ्तरों में बैठे-बैठे ट्रेनों में, पटरियों की सुरक्षा में, खान-पान सेवा में कहां-कहां कमियां हैं, उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और उसी के अनुरूप वे काम करते हैं तथा कर्तव्यों का निर्वहन करते रहते हैं। अप्रत्याशित

घटना या दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफा देकर अलग होते हुए रेल मंत्री को तो हमने देखा व सुना है, जो कि इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है, परन्तु रेलवे बोर्ड के सदस्य विभिन्न कार्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हुए भी अब तक नैतिक आधार पर कोई स्वेच्छा से उनके पद त्याग की बात कभी नहीं सुनी है। सभी जिम्मेदारी अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर डाल दी जाती है और बड़े अधिकारी अपने दायित्वों से बच निकलते हैं। उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों पर पहले कार्यवाही ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप प्रश्न पूछिए क्योंकि समय कम है।

श्री भगत राम मनहर : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के सदस्यगण यदि ट्रेनों से सफर करना शुरू करें तो बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। कई ट्रेनों में खान-पान का ठेका दे दिया गया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : सजेशंज के साथ आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि समय कम है। अन्यथा उत्तर नहीं मिल पाएगा।

श्री भगत राम मनहर : रेलवे अधिकारियों की मिली-भगत से ठेका नियमों का सही पालन नहीं हो रहा है और जो वहां कर्मचारी हैं, वे कमीशन के आधार पर काम कर रहे हैं, बहुत सी ट्रेनों में तो वे कमीशन के बेसिस पर काम कर रहे हैं और आपके श्रमिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है, खान-पान में दुर्व्यवहार हो रहा है, सर्विसेज ठीक नहीं हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके सुधार के लिए आपने कौन-कौन सी योजनाएं बनाई हैं ?

श्री नीतीश कुमार : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न की भूमिका में जो कुछ भी कहा, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझाता और अधिक से अधिक लोग ट्रेन से यात्रा करें, वह स्वागत योग्य होगा। मैं तो सबसे ज्यादा ट्रेन से ही चलता हूं, चाहे यह विभाग रहे या कोई अन्य विभाग रहे, चाहे विभाग रहे भी या नहीं रहे, चाहे कोई भी कैपेसिटी हो और जो माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, उनका भी बगैर ट्रेन के काम नहीं चल सकता है। सब लोग यात्रा करते हैं और सब के अपने खट्टे मीठे अनुभव ट्रेन में होते हैं। कुछ अच्छे अनुभव होते हैं और कुछ असंतोष पैदा करने वाले अनुभव होते हैं इसमें कोई दो राय नहीं हैं। अब प्रश्न चूँकि खान-पान सेवा से संबंधित हैं, खान-पान सेवा में निरन्तर सुधार हो यह हमारा प्रयत्न होगा। खान-पान सेवा में एक जमाने से ही निजी क्षेत्र के लोगों की भी भागीदारी रही है। खान-पान सेवा दो-तीन तरह की है। एक तो कुछ ट्रेनों में जो खान-पान सेवा दी जाती है उसमें पेंट्री कार वगैरह लगायी जाती हैं, कुछ जो बड़े या छोटे रेलवे स्टेशन हैं, उन पर रेफ्रेशमेंट रूम्ज होते हैं। इसके अलावा वेंडर्ज होते हैं, सटाल्ज लगते हैं। जहां तक पेंट्री कार्ज या बड़े स्टेशनों पर रेफ्रेशमेंट रूम्ज अलाट करने का सवाल है ।.... जो पहले की पॉलिसी थी, उसमें कुछ बदलाव

लाया गया है। वर्ष 1999 में बजट भाषण में ही हमारी ओर से उल्लेख किया गया था कि इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए उसमें 2 पैकिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। पहले जो ठेका दिया जाता था, उसमें टेंडर इनवाइट किया जाता है, एलिजिबिलिटी तय की जाती है और उसके बाद उसका जो एक बेस प्राइस तय किया हुआ है कि टर्न-ओवर पर वह कम से कम इतना प्रतिशत वह देंगे, उस आधार पर जो कोई भी ज्यादा से ज्यादा देने को तैयार होता है, उस को टेंडर दिया जाता है। नयी टेंडर प्रणाली से लाभ बढ़ा है और नई पॉलिसी से पहले से कुछ ज्यादा आमदनी बढ़ी है। अब चूंकि रेलवे में दोनों प्रकार से अर्थात् विभाग की तरफ से भी कैटरिंग सेवा है और रेलवे भी अपनी सेवा चलाती है व प्राइवेट सेक्टर को यह ठेके पर भी कार्य देती है इसलिए दोनों सेवाएं चल रही हैं । अभी माननीय सदस्य ने कुछ कमीशन एजेंटस की बात की। उसके संबंध में कोर्ट ने कुछ आदेश दिया था, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को इसमें आब्जर्व किया गया है और किया जा रहा है।

श्री भगतराम मनहर : सर, ठेका देते समय कोई ऐसा नियम है कि ठेकेदार अपने कर्मचारी को नियमित रखेंगे क्योंकि उन्होंने किसी कर्मचारी को नियमित नहीं रखा है। खासकर सम्बलपुर एक्सप्रेस में जो ठेकेदार चल रहे हैं, उन्होंने सभी कर्मचारी टेंपरेरी रखे हैं। वह उन्हें रोज हटा देता है। आप दूसरी बार आएंगे तो दूसरा दिखाई देता है, ठेकेदार जो चाहता है, व्यवहार करता है और उसकी सर्विस भी ठीक नहीं है। उसके कार्य के संबंध में आपके अधिकारियों ने कभी जांच नहीं की और न कभी उसकी देखरेख की। इसी तरह जहां तक खान-पान का सवाल है, राजधानी एक्सप्रेस में भी साउथ का है, वह थोड़ा ठीक है और बाकी सभी में खान-पान की स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके बारे में भी आपके अधिकारियों ने कभी जांच नहीं की। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप जैसे कि हवाई जहाजों में इनफ्लाइट सर्विसेस हैं, उसी तरह आप ऑटोनामस बॉडी बनाएंगे ताकि उनमें खान-पान की सेवाओं में सुधार हो और ठेकेदारों पर भी ठीक तरह से नियंत्रण हो सके ? महोदय, यह सभी की शिकायत है कि खान-पान का स्तर पहले से बहुत नीचे चला गया है और शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। वह पत्र महीनों तक आप के कार्यालय में पड़ा रहता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : चलिए प्रश्न पूछिए। मंत्री जी ने आपके सजेशंस नोट कर लिए हैं।

श्री नीतीश कुमार : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने कमीशन एजेंट्स के बारे में कहा था, वे रेलवे की डिपार्टमेंटल कैटरिंग के साथ कमीशन बेसिस पर जुड़े हुए थे। उनके संबंध में मैंने कहा है कि कोर्ट ने आदेश दिया था, उनकी सेवा नियमित की गयी है और जो बचे हैं, उनकी की जा रही है। लेकिन जो प्राइवेट कैटरर्स हैं और उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनके संबंध में कोई नियम नहीं है। हां, यह जरूर है कि वे ट्रेंड होने चाहिए, उनका व्यवहार ठीक होना चाहिए, उनकी

हैल्थ ठीक होनी चाहिए और उनकी ड्रेस ठीक होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस दी गयी हैं, लेकिन जो प्राइवेट कैटरर्स हैं, वे अपने एम्पलाई को किस टर्म पर बहाल करता है, इस बारे में रेलवे की तरफ से कोई बात नहीं देखी जाती है। उसे देखने के और लेबर लॉज हो सकते हैं, दूसरे कानून हो सकते हैं, लेकिन यह हमारे यहां उस आधार पर नहीं होता है। जहां तक खान-पान सेवा में इम्प्रूवमेंट का सवाल है, इसके लिए आप जो भी सुझाव देंगे, उसका मैं स्वागत करूंगा, उस पर गौर करूंगा इतना ही कह सकता हूं। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि कम्प्लेंट डिस्पोजल के भी कई सिस्टम बने हुए हैं। जब भी कम्प्लेंट आती हैं तो लोग उसे देखते हैं और उसकी जांच करते हैं। यह सब व्यवस्था तो है और व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका अनुपालन कितना हो रहा है, यह एक विचारणीय विषय हो सकता है। इसलिए माननीय सदस्य जो भी रचनात्मक सुझाव देंगे मैं उनको इतना आश्वस्त करूंगा कि मैं उन सुझावों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करूंगा।

SHRI GOPAL SINH G. SOLANKI : I have just one small question. Sir. Looking at Annexure-II, we find that the contracts have been given for unlimited time. Does the Railway Administration think this is right? Secondly, most of the caterers seem to be inheriting the business. Would they prevent this?

श्री नीतीश कुमार : सर, माननीय सदस्य के प्रश्न में कोई ऐसी बात नहीं है, इस संबंध में मैंने पूरा जबाव दे दिया है। वहां 51 कैटरर्स 124 ट्रेंस पर हैं। इस तरह एक से अधिक ट्रेन पर एक कैटरर होगा तभी तो वह कैटरिंग कर सकता है। इसका मतलब है कि उनको एक से अधिक ट्रेन मिली होगी। लेकिन नई पालिसी में 5 साल के लिए कांट्रेक्ट होगा, अगले 5 साल के लिए उन का रिनुएबल होगा। जो माइनर कांट्रेक्टस हैं वे तो 5 साल के लिए ही हैं यानी मेजर कांट्रेक्टस में 10 साल के बाद फिर से पूरा का पूरा प्रोसीजर होगा। अनलिमिटेड पीरिएड के लिए नई कैटरिंग पॉलिसी में प्रावधान नहीं है।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Formulation of decisions on education

*561. SHRI NANA DESHMUKH : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether, under the present mechanism, all the State Governments had been participating in the formulation of major decisions in matters of education and give them the status of national decisons;